विस्थापितों के हक के लिए होता रहेगा आंदोलन

दुमका | प्रतिनिधि

माइंस,मिनरल एवं पीपल संगठन का दो दिवसीय सम्मेलन गुरुवार को एसडीसी कार्यालय, दुधानी में आयोजन किया गया। जिसमें देश भर के अन्य राज्यों से कोल विस्थापित संगठनों के प्रतिनिधि ने भाग लिया।

सम्मेलन में कोल ब्लाक क्षेत्र के विस्थापितों को पुनर्वास की व्यवस्था, विस्थापितों के अधिकार शिक्षा, स्वास्थ व्यवस्था करने, पर्यावरण मित्रवत खदानों को शुरू करने को लेकर चर्चा किया गया। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, झारखंड के के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि कोल ब्लॉक से विस्थापितों को जब तक अधिकार नहीं मिल जाता और समस्या का हल नहीं हो जाते आंदोलन को क्षेत्रीय स्तर से लेकर देश भर में जारी रखा जाएगा।

सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि पहला आंदोलन छतीसगढ़ के काले में

गुरुवार को दो दिवसीय सम्मेलन को सम्बोधित करते अतिथि। • हिन्दुस्तान

जिंदल कंपनी के विरूद्ध 2 अक्टूबर 2013 में किया गया था। दूसरा उड़ीसा के अंगुल में मार्च-अप्रैल के माह में किया गया। तीसरा दुमका में गुरूवार को आंदोलन की दिशा और रणनीति तय करने के लिए सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 212 कोल ब्लाक को रद्द किया गया जो 20 वर्षो से गलत तरीके से चल रहा था। जिसमें 186 हजार करोड़ का सरकार को राजस्व की क्षति पहुंची थी। एक अन्य मामले में 40 खदानों में जो वर्तमान में काम चल रहा है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार छह माह के अंदर बंद करने का निर्देश दिया। कोर्ट द्वारा 31 मार्च 2015 तक बंद करने का निर्देश दिया गया था। अन्य 6 में एक एनटीपीसी कोल ब्लाक को छोड़कर बाकी को रद्द

सम्मेलन

- दुमका में माइंस,मिनरल एवं पीपल संगठन का सम्मेलन शुरू
- सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, झारखंड के के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं

करने की बात सम्मेलन द्वारा किया जा रहा है। अंत में सम्मेलन में बंदी अधिकार के राष्ट्रीय समन्वयक संतोष उपाध्याय ने बताया कि स्थानीय कानूनों के अनुसार निजी कंपनियों के द्वारा गैर कानूनी ढ़ंग से खनन का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को उनके फर्जी मुकदमे कर जेलों में डालने का विरोध करते हुए कहा कि आंदालनकारियों के तमाम मुकदमें हटाकर उन्हें मुक्त किया जाये। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राय मुर्ति श्रीधर, उपाध्यक्ष अशोक श्रीबालि, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य मुन्नी हांसदा के साथ देश भर से आये विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सरल एवं सुगम बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भरने के लिए जानकारी प्रचार-प्रसार के माध्यम से करने पर बल दिया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा हर माह में प्रखंडवार केसीसी बैठक करने एवं बैठक में बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा केसीसी सी संख्या बढ़ाने के लिए प्रबंधक, अग्रणी बैंक से आवश्यक सहयोग की आशा व्यक्त की गई।

मजदूरों के भुगतान की समस्या दूर करें: डीसी

दुमका | प्रतिनिधि

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा मनरेगा अन्तर्गत डाक विभाग,बैंक,जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त हर्ष मंगला ने गुरुवार को एक बैठक की।

बैठक में उपायुक्त श्री मंगला ने कार्यशाला के दौरान कहा कि मनरेगा आयुक्त के आदेशानुसार इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मजदूरों के भुगतान से संबंधित एफटीओ की समस्या का निदान कराना आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारियों से यह अपील की कि वे सभी प्रकार की समस्याओं को इस कार्यशाला में रखेंगे एवं उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। वरीय डाक अधीक्षक ने कहा कि डाकघर मनरेगा में एक सेवा प्रदाता का कार्य करती आ रही है, लेकिन किसी भी कार्य के शत-प्रतिशत सफलता के लिए परस्पर सहयोग की जरुरत है। इस अवसर पर संताल परगना के सभी उपविकास आयुक्त,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी पदाधिकारियों ने अपने जिले एवं प्रखंड से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। बैंक एवं डाक घर के पदाधिकारियों ने आवयक जानकारी दी।